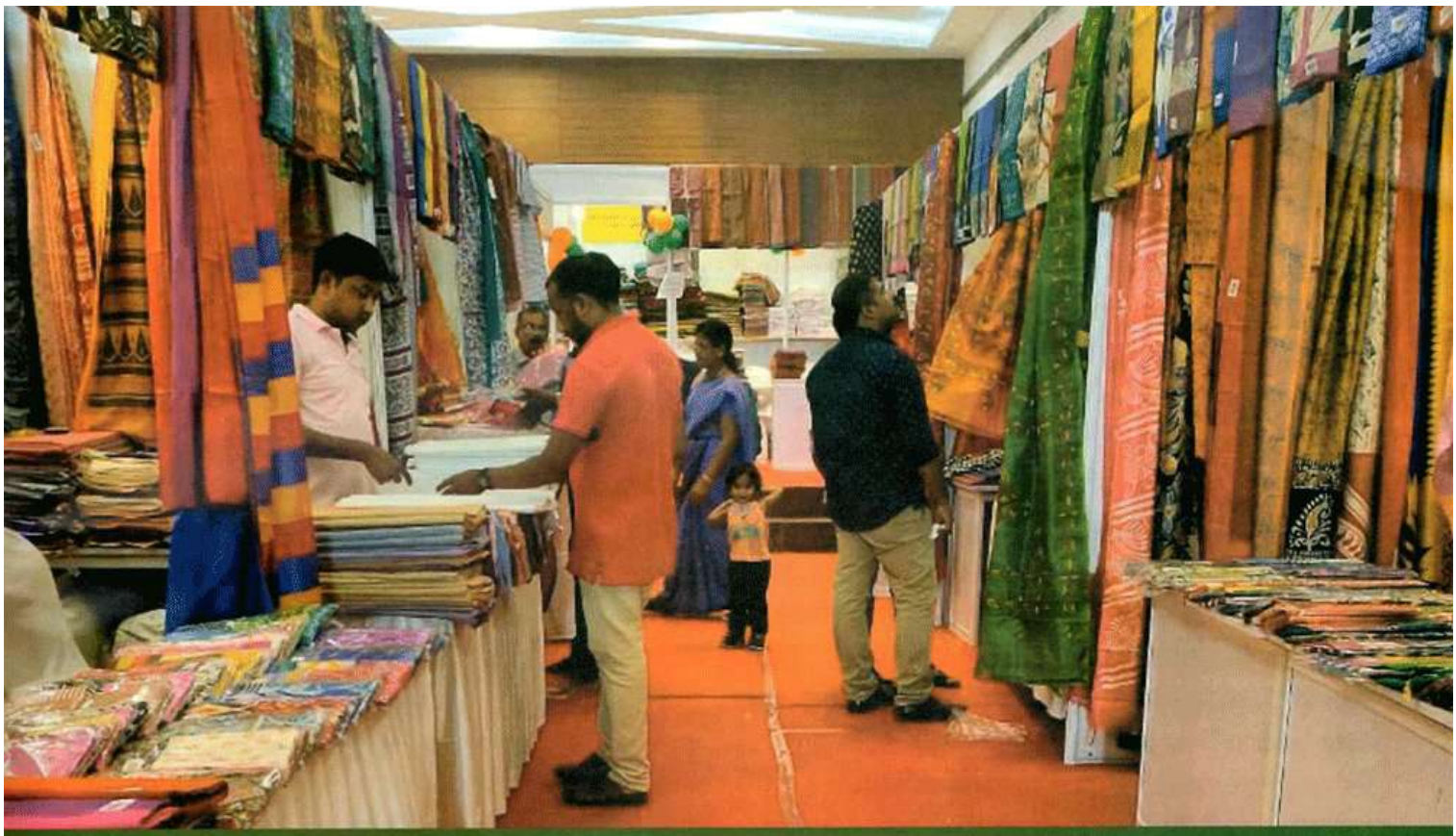

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करती खादी

शिशिर सिन्हा

खादी भारत के समावेशी आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। खादी में स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने से लेकर एक आधुनिक आर्थिक चालक के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तन आया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण प्रयासों का नेतृत्व किया है, परिणामस्वरूप इसकी बिक्री में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 और वर्ष 2024-25 के बीच, खादी के उत्पादन में लगभग चार गुना वृद्धि हुई, जबकि बिक्री में लगभग छह गुना वृद्धि हुई। खादी क्षेत्र वर्तमान में लगभग पाँच लाख कारीगरों को रोज़गार प्रदान करता है, जिसमें इस कार्यबल का 80 प्रतिशत हिस्सा महिलाएँ हैं।

भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है और अगले 22 वर्षों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य (वर्ष 2027 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2030 तक 7 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2033 तक 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था यानी विकसित देश) तय कर लिए गए हो तो ऐसे में जरूरी है कि विकास के मायने आँकड़ों तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि जमीनी स्तर पर उसका व्यापक और व्यावहारिक असर दिखे। यही स्वदेशी माध्यमों की महत्ता बढ़ाता है और विकास का फायदा जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनता है। यही समानता और समावेशी विकास का आधार ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा भी है। खादी ऐसा ही एक स्वदेशी माध्यम बन रही है।

यहाँ यह समझना जरूरी है कि खादी को स्वदेशी माध्यम कहने के पीछे आधार क्या है? इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत खादी की परिभाषा देखनी होगी। अधिनियम कहता है, 'खादी से भारत में हाथ से काते गए सूती, रेशमी या ऊनी धागे से अथवा ऐसे सब धागों या उनमें से किसी दो के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुना कोई कपड़ा अभिप्रेत है।' इस परिभाषा का ताना-बाना संभवतः महात्मा गाँधी

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। ईमेलः hblshishir@gmail.com

की ओर से खादी की दी गई परिभाषा के आधार पर तैयार किया गया जिसमें कहा गया: 'हाथ से काते हुए सूत से बना और हाथ से बुना कपड़ा, चाहे वह कितना भी उत्तम क्यों न हो, खादी ही है। यह सूती, रेशमी या ऊनी भी हो सकता है। इनमें से जो भी सुविधाजनक लगे, उसे पहनना चाहिए। आंध्र प्रदेश की खादी बहुत उत्तम होती है। असम में रेशमी खादी मिल जाती है। ऊनी खादी काठियावाड़ में बनती है। दूसरे शब्दों में, खादी का एकमात्र मानदंड यह है कि वह हाथ से काती और बुनी गई हो।'

गाँधी जी के प्रोत्साहन की आज़ादी पूर्व आर्थिक ताने-बाने में खादी की तो अहमियत रही ही, वहीं इस सिलसिले को आज़ादी के बाद भी तत्कालीन सरकार ने आगे बढ़ाया। इस कोशिश को और भी बल मिला जब एक कानून के तहत एक विशिष्ट आयोग (खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी) बना और उसके ज़रिए खादी के उत्पादन में लोगों के प्रशिक्षण, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, वित्तीय संसाधन और विपणन को बढ़ावा देने का खाका खींचा गया। यह इसीलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के हस्त-कारीगरों की एक ध्यान देने वाली संख्या खादी तैयार करने में लगी थी लेकिन उनके लिए बाज़ार तक पहुँचना आसान नहीं था जिसे आयोग ने दूर करने की कोशिश की।

और यही कोशिश अब रंग ला रही है। यकीन ना हो तो इन आँकड़ों पर नज़र डालिए। खादी कपड़ों का उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के करीब 811 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3700 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया यानी करीब साढ़े चार गुना की बढ़ोत्तरी हुई। दूसरी ओर बिक्री की बात करें तो जहाँ वित्त वर्ष 2013-14 में यह आँकड़ा करीब हजार करोड़ रुपये का था जो वित्त वर्ष 2024-25 में 7000 करोड़ रुपये के पार हो गया यानी करीब साढ़े छह गुना की बढ़ोत्तरी हुई। रोज़गार की बात करें तो खादी क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोग कार्यरत है जिनमें खादी कताईकर्ता, बुनकर, खादी कार्यकर्ता और वस्त्र निर्माण के बाद उत्पादन, परिधान रूपांतरण और बिक्री कार्यकलापों के संलग्न अन्य कारीगर शामिल हैं। गौर करने की बात यह है कि विभिन्न योजनाओं के तहत खादी क्षेत्र में महिला कारीगरों की भागीदारी करीब 80 प्रतिशत है।

अब बाज़ार के चलन के हिसाब से चलने की तैयारी है। शायद यही वजह है कि भले ही देशभर में आयोग के 24 केंद्रों के साथ छोटे-बड़े दुकानों व शोरूम के ज़रिए खादी की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब आयोग नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित अपने केंद्र को देश के पहले खादी मॉल (कपड़ों के लिहाज़ से) में तब्दील करने जा रहा है। करीब 20 हजार वर्गफुट इलाके में विकसित हो रहे इस मॉल का खास आकर्षण आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एआई मॉडल होगा। आदमकद शीशेनुमा यह मॉडल सामने खड़ा होने पर बताएगा कि उन पर कौन से रंग और डिज़ाइन के परिधान फबेंगे।

आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार की माने तो यह मॉल बापू महात्मा गाँधी के सपनों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न का स्वरूप दिखाएगा। ध्यान रहे कि मौजूदा स्वरूप में आयोग का यह केंद्र प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हासिल कर चुका है और अकेले यहाँ सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये के पार हो चुका है।

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि खादी को बस घरेलू बाज़ार तक सीमित नहीं रखना है। इसीलिए इसे विदेशों में पहचान दिलाने के प्रयास किए गए। इसका पहला परिणाम जुलाई 2017 में देखने को मिला जब आयोग ने पूरे विश्व में खादी डेनिम उत्पादों का व्यापार करने के लिए अरविन्द मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अमेरिका के फैशन ब्रान्ड पैटागोनिया ने खादी डेनिम कपड़ा खरीदने के लिए बार-बार ऑर्डर दिया। पहली बार में 1.08 करोड़ रुपये मूल्य के खादी डेनिम कपड़े के 30,000 मीटर का ऑर्डर आया, फिर उसके बाद अरविन्द मिल्स के माध्यम से गुजरात के राजकोट स्थित खादी संस्थान से लगभग 80 लाख रुपये मूल्य के 17,050 मीटर खादी डेनिम कपड़ा खरीदने का ऑर्डर मिला।

खादी वस्त्र बने नए फैशन स्टेटमेंट!

प्रधानमंत्री द्वारा बड़े मंच से खादी को बढ़ावा देने से खादी कपड़ों की बिक्री में तेज़ी से उछाल आया है।

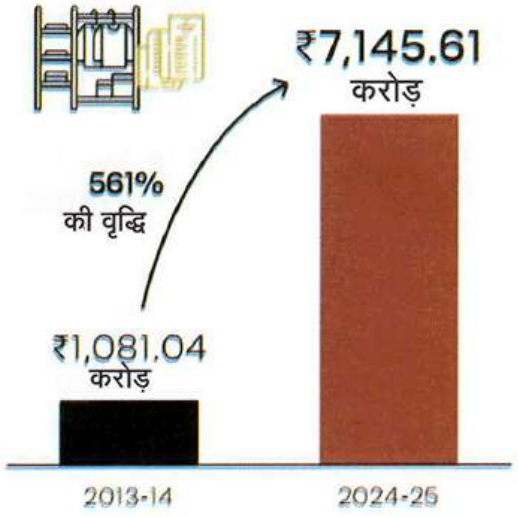

तालिका – खादी क्षेत्र में रोजगार
(31 मार्च, 2024 की स्थिति)

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	कुल रोजगार
जम्मू व कश्मीर	21,921
हिमाचल प्रदेश	2,278
पंजाब	5,191
चंडीगढ़	54
हरियाणा	56,085
दिल्ली	1,180
राजस्थान	30,651
उत्तराखंड	18,078
उत्तर प्रदेश	1,37,149
छत्तीसगढ़	6,179
मध्य प्रदेश	3,707
सिक्किम	28
अरूणाचल प्रदेश	31
नगालैंड	295
मणिपुर	168
मिज़ोरम	12
त्रिपुरा	25
मेघालय	59
असम	5,125
बिहार	72,755
पश्चिम बंगाल	32,831
झारखंड	1,875
ओडिशा	5,347
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
गुजरात	18,964
महाराष्ट्र	3,091
गोवा	0
आंध प्रदेश	9,092
तेलंगाना	2,347
कर्नाटक	27,708
केरल	14,339
तमिलनाडु	20,464
पुडुचेरी	465
कुल	4,98,594

स्रोत – राज्यसभा प्रश्नोत्तर

देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खादी के स्टोर खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में संभावनाएं तलाशने के लिए आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल थाईलैंड का दौरा कर चुका है। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर ब्रांड 'खादी' की पहचान बनाए रखने के लिए, आयोग ने 15 देशों में ट्रेडमार्क के लिए और 31 देशों में प्रतीक चिह्न (Logo) के लिए पंजीकरण कराया है। इन प्रयासों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खादी का कुल निर्यात 37.88 करोड़ रुपये का हुआ। भारत में मुख्य रूप से खादी का निर्यात चीन, रूस और तंजानिया को होता है।

बीते 11 वर्षों के दौरान खादी के विपणन के साथ ही खादी कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और अब कोशिश है कि इन प्रयासों में तेज़ी लाई जाए। ऐसे ही कुछ प्रयासों पर नजर–

उत्पादन व्यवस्था सुधारने के कदम

- एक लच्छे के लिए कताई मजदूरी 10 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये की गई। साथ ही, सूती खादी, ऊनी खादी और पॉली वस्त्र के लिए बुनाई मजदूरी 7 फीसदी बढ़ायी गई।
- संशोधित बाज़ार विकास सहायता के तहत सूती, ऊनी, पॉली वस्त्र की खादी संस्थाओं में कामगारों को 35 फीसदी और रेशम के खादी संस्थानों के मामले में 30 फीसदी की दर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- एक विशेष योजना के तहत छायादार कार्यस्थल बनाने के लिए कारीगरों को व्यक्तिगत स्तर पर कुल लागत का तीन-चौथाई या 1.20 लाख रुपये, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता मिलती है। दूसरी ओर, समूह (कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 कारीगर) के तहत 80 हजार रुपये प्रति कारीगर या फिर कुल लागत के तीन चौथाई के बराबर की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- खादी विकास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र के ज़रिए खादी संस्थाओं को बैंक से 4 फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज़ मिलेगा। वास्तविक ब्याज दर और 4 फीसदी के बीच का अंतर भारत सरकार, आयोग के ज़रिए सब्सिडी के तौर पर मुहैया कराती है।
- कमजोर खादी संस्थाओं को सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रति बिक्री केंद्र 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

देश-विदेश के बाज़ारों में विपणन के कदम

- वैश्विक मानकों के लिए बेंचमार्क डिज़ाइन प्रक्रिया की स्थापना, नए कपड़े और उत्पाद बनाने, कपड़ों के गुणवत्ता मानकों का प्रचार-प्रसार, नई खादी की ब्रांडिंग और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैशन शो और प्रदर्शनी के लिए हब व स्पोक मॉडल के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के साथ केंद्र स्थापित किए गए हैं।

- विक्रेता से उपभोक्ता को उत्पाद बेचने के उद्देश्य से जेम पोर्टल और ई-मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु व मझोले कारोबारियों के लिए ई-मार्केट लिंकेज की सुविधा विकसित की गई।
- खादी के पारखी व डिज़ाइनर को आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरों में विशेष खादी लाउंज की स्थापना की गई है।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की ओर से पूरे वर्ष के दौरान आवश्यक हथकरघा वस्त्रों की कुल खरीद में कम से कम 20 फीसदी की खरीद खादी के रूप में करने की शर्त रखी गई है।
- चादर व तकिए समेत विभिन्न खादी उत्पादों की आपूर्ति रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अर्धसैनिक बलों की की जा रही है।

निष्कर्ष

खादी को लेकर सोच बदली है और अब यह हर पीढ़ी और समाज के हर तबके को लुभा रही है और यही खादी की अर्थव्यवस्था के विस्तार में मददगार साबित हो रही है। खास बात यह भी है कि समय-समय पर प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्री की अपील ने भी लोगों को खादी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि हर परिवार 5 हज़ार रुपये की खादी हर साल ज़रूर खरीदे। उन्होंने कहा कि इससे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खादी शरीर, गरीब के घर और देश के अर्थतंत्र को फायदा पहुँचाती है।

उधर, वर्ष 2025 की गाँधी जयंती से पहले प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में अपील की: "गाँधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और इनमें खादी सबसे प्रमुख थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद, खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी, लेकिन बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। आप सभी से आग्रह है कि 2 अक्तूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें। गर्व से कहें – ये स्वदेशी है।" ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

मासिक पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन मूल्य सूची

क्र॰ सं॰	पत्रिकाओं का नाम	प्रिंट क्षेत्र (वर्ग सेमी. में) चौ॰ x ऊँ॰	आंतरिक पृष्ठ				पार्श्व आवरण	दूसरा आवरण	तीसरा आवरण
			पूरा पृष्ठ (रंगीन)	आधा पृष्ठ (रंगीन)	पूरा पृष्ठ (श्वेत श्याम)	आधा पृष्ठ (श्वेत श्याम)	पूरा पृष्ठ (रंगीन)	पूरा पृष्ठ (रंगीन)	पूरा पृष्ठ (रंगीन)
			पत्रिकाओं के एक अंक में उल्लिखित स्थान के लिए मूल्य रुपये में						
1.	योजना (अंग्रेजी)	17 x 23	35000	20000	25000	15000	100000	70000	70000
2.	योजना (हिंदी)	17 x 23	25000	15000	18000	11000	75000	50000	50000
3.	कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी/हिंदी)	17 x 23	20000	12000	15000	10000	30000	27000	25000
4.	योजना (गुजराती/मलयालम/पंजाबी/असमिया/उर्दू/ओडिया)	18 x 23	7000	4500	5000	3000	10000	9000	8000
5.	योजना (तेलुगु/तमिल/कन्नड/बंगाली/मराठी)	18 x 23	13000	8000	10000	6000	20000	17000	15000
6.	आजकल (हिंदी/उर्दू)	11.5 x 19	10000	6000	7000	5000	15000	12000	11000
7.	बाल भारती (हिंदी)	15.5 x 20.5	10000	---	---	---	15000	12000	11000

विज्ञापनों की बुकिंग के लिए या विज्ञापनों के मूल्य, कमीशन और छूट से संबंधित किसी अन्य जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कृपया प्रसार एकक, प्रकाशन विभाग से ईमेल sec-circulation-moib@gov.in या फोन 011-24365610/24367453 द्वारा सीधे संपर्क करें।